

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट दूदू

बिजलास :- डॉ. अर्तिका शुक्ला (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 11/2018 पुनः दर्ज नम्बर 04/2023 (रसद अपील)

मैसर्स ग्राम सेवा सहकारी समिति लसाडिया विक्रेता उचित मूल्य दुकान ग्राम पंचायत लसाडिया तहसील फागी जिला जयपुर हाल जिला दूदू जरिये फर्म व्यवस्थापक श्री प्रभू सिंह

(अपीलार्थी)

बनाम

जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय जयपुर

(प्रत्यर्थी/विपक्षी)

अपील अन्तर्गत धारा 22 (1) (2) राजस्थान खाद्यान्न एवं आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1978 विरुद्ध आदेश जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय के प्रकरण संख्या 250/2017 निर्णय दिनांक 20.12.2017 जिसके द्वारा अपीलार्थी की उचित मूल्य की दुकान का प्राधिकार पत्र निरस्त कर धरोहर राशि 250/-रुपये जब्त सरकार करने के आदेश पारित किया गया।

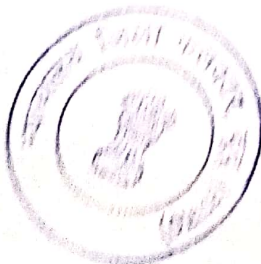
समाप्ति :-

1. श्री शिवराम शर्मा / मनोज कुमार नाथावत अपीलार्थी की और से।
2. जिला रसद अधिकारी दूदू प्रत्यर्थी/विपक्षी की और से।

निर्णय

दिनांक :- 13.2.2024

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी मैसर्स ग्राम सेवा सहकारी समिति लसाडिया प्राधिकृत विक्रेता उचित मूल्य दुकान ग्राम पंचायत लसाडिया तहसील फागी का प्राधिकार पत्र निरस्त कर धरोहर राशि 250/- रुपये जब्त सरकार करने के आदेश से व्यथित होकर अपील पेश की गई है।



जिला कलक्टर
दूदू (राजग)

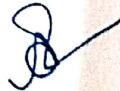
2. यह अपील जिला कलक्टर जयपुर से नवसृजित जिला दूदू के क्षेत्राधिकार की होने से पत्रावली जिला कलक्टर जयपुर से इस न्यायालय में स्थानान्तरित होने से अपील पुनः दर्ज रजिस्टर की जाकर अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी/प्रतिवादी को नोटिस जारी किया गया। तहत रिकार्ड पूर्व से ही संलग्न पत्रावली है। प्रत्यर्थी की ओर से जिला रसद अधिकारी दूदू उपस्थित है। अपीलार्थी की तरफ से श्री उनके अधिवक्ता श्री शिवराम शर्मा व मनोज कुमार नाथावत उपस्थित आये।

3. बहस उभयपक्ष सुनी गई।

4- अपीलार्थी के अधिवक्ता ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलार्थी मैसर्स ग्राम सेवा सहकारी समिति लसाडिया प्राधिकृत विक्रेता उचित मूल्य दुकान ग्राम पंचायत लसाडिया जिला दूदू का प्राधिकार धारक दुकानदार है, जिसे राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के प्रावधानों के तहत प्राधिकार पत्र मिला हुआ था। अपीलार्थी उक्त आदेश 1976 एवं प्राधिकार पत्र की शर्तों व निर्बन्धनों, सरकार के अधिसूचित आदेशों एवं सक्षम अधिकारियों के निर्देशानुसार उचित मूल्य की वस्तुओं का वितरण नियमानुसार करता है। दिनांक 26.8.2017 व 7.9.2017 को प्रवर्तन अधिकारी फागी द्वारा जाँच कर 15.64 क्विंटल गेहूँ एवं 227.50 लीटर केरोसीन तेल का दुरुपयोग किया जाना बताकर मेरे विरुद्ध कार्यवाही कर जिला रसद अधिकारी महोदय ने दिनांक 20.12.2017 को आदेश पारित कर मेरे प्राधिकार पत्र को निरस्त कर दिया गया है, जाँच दल ने दिनांक 26.8.2017 को निरीक्षण कर फर्द मौका तैयार कर जाँच कर ली थी लेकिन उसके बाद 10 दिन पश्चात पुनः जाँच की गई उसके पश्चात दिनांक 4.10.2017 को जाँच दल ने जिला रसद अधिकारी जयपुर को रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। जाँच के दौरान अपीलार्थी को नहीं सुना गया। निष्पक्ष जाँच नहीं की गई। अपीलार्थी के विरुद्ध बदनियती व दुर्भावना रखी गई है। जिला रसद अधिकारी जयपुर ने भी अपीलार्थी को जवाब व दस्तावेजी साक्ष्य पेश करने का अवसर नहीं दिया गया। एकतरफा निर्णय पारित किया गया है। जबकि न्यायिक सिद्धान्त के अनुसार अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर दिया जाना जरूरी था। जाँच दल ने जिन उपभोक्ताओं के बयान दर्ज किये हैं उन सभी ने शपथ पत्र पेश कर बताया है कि राशन डीलर से हमें कोई शिकायत नहीं है। जिला रसद अधिकारी महोदय जयपुर ने अपीलार्थी को सुनवाई हेतु अवसर नहीं दिया है एकतरफा आदेश पारित किया गया है। इसलिए अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.12.2017 को अपास्त फरमाया जाकर प्राधिकार पत्र एवं प्रतिभूति राशि बहाल किये जाने के आदेश फरमावे।

5. प्रत्यर्थी/प्रतिवादी की ओर से जिला रसद अधिकारी दूदू ने अपीलार्थी के तर्कों का खण्डन करते हुए निवेदन किया कि अपीलार्थी द्वारा 15.64 क्विंटल गेहूँ, 227.500 लीटर केरोसीन का दुरुपयोग किया गया है। अपीलार्थी ने प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 2, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 14.17 (सी) एवं 18 का स्पष्ट उल्लंघन किया है। इसलिए जिला रसद अधिकारी जयपुर




जिला कलक्टर
दूदू (राज0)

द्वितीय द्वारा पारित आदेश उचित है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील छारिज फरमाई जावे।

6. उभयपक्ष की बहस को गौर से सुना गया एवं उस पर मनन किया। पत्रावली का भलीभांती अवलोकन किया गया।

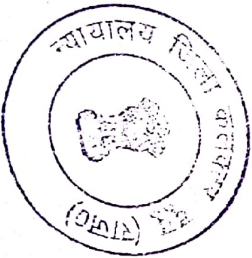
7. अपीलार्थी पर मुख्य आरोप है कि उसने 15.64 क्विंटल गेहूँ व 227.50 लीटर केरोसीन तेल का दुरुपयोग किया है। जबकि अपीलार्थी का कथन है कि उसको साक्ष्य दस्तावेज पेश करने का मौका नहीं दिया गया है। अधिनस्थ न्यायालय ने एकतरफा आदेश पारित किया है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर अपीलार्थी की उपस्थिति के हस्ताक्षर तो हैं लेकिन जवाब/दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। वकील अपीलार्थी द्वारा दस्तावेज सूची के साथ प्रस्तुत शपथ पत्रों के अनुसार गवाहों ने भी अपीलार्थी से उन्हें कोई शिकायत नहीं होना बताया है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से अपीलार्थी को साक्ष्य/सबूत पेश कर सुनवाई का अवसर नहीं देना जाहिर होता है। उपरोक्त तथ्यों के विवेचन से अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर दिया जाना न्यायहित में उचित मानते हुए, अपील स्वीकार किया जाना न्यायोचित समझते हैं।

8. जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय द्वारा पारित अपीलार्थीन निर्णय दिनांक 20.12.2017. को निरस्त किया जाता है अपीलार्थी जीलर का प्राधिकार पत्र व धरोहर राशि बहाल किये जाने का आदेश दिये जाते हैं।

9. जिला रसद अधिकारी दूदू को प्रकरण प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि यदि कोई अनियमितता मानते हैं, तो प्रकरण में पुनः जांच कराकर एवं अपीलार्थी को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने का समुचित अवसर प्रदान कर नये सिरे से विधि सम्मत आदेश पारित करें।

10. निर्णय की प्रति मय मिसल मातहत जिला रसद अधिकारी दूदू को प्रेषित हो। पत्रावली बाद तकमील फ़ैसल शुमार होकर दाखिल दफ़तर हो।

11. निर्णय आज दिनांक 13.2.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।



(डॉ० अर्तिका शुक्ला)

जिला कलेक्टर

जिलामुद्रकालयदर

दूदू (राज०)